SOCIO-ECONOMIC RESEARCH INSIGHTS
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
समाजिक-आर्थिक अनुसंधान अंतदृष्टि
सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका

SERI 2026; 1(1): 05 Received: 25-01-2026 Accepted: 28-01-2026

बिहार की अर्थव्यवस्था में कुटिर उद्योग की भूमिका

दिलीप कुमार पोद्दार
शोध–छात्र
विश्वविधालय ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं
सहकारी प्रबंधन विभाग
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय
भागलपुर– 812007 (बिहार)

सार

भारत में प्राचीन समय से ही लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रधानता रही हैं। आज से दो हजार वर्ष पूर्व भी भारत का सूती वस्त्र एवं इस्पात उद्योग विश्व में प्रसिद्ध था। आज विकसित या विकासशील देशों में छोटे उद्योगों की उपयोगिता और भी अधिक हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ आज भी 72.2 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती हैं और जहाँ पूंजी का अभाव हैं तथा जनशक्ति की अधिकता हैं वहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के बिना बहुसंख्यक ग्रामीणों की आर्थिक समस्याओं का निवारण नही किया जा सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी विनियोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता हैं और साथ ही अधिकाधिक संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता हैं यही नहीं लघु एवं कुटीर उद्योगों अधिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करके आय उवं संपत्ति की असमानताओं को कम करने में भी सहायक हैं तथा आर्थिक गतिविधियों के द्वारा प्रादेशिक असंतुलनों को भी कम करते हैं ये ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने माल का लाभ प्रदान करके अपनी रूचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने में सहयोग देते हैं।

कुंजी शब्द– विकासशील, जनशक्ति, बहुसंख्यक, केंद्रीकरण, आर्थिक गतिविधियों, प्रादेशिक असंतुलनों

परिचय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की जनसंख्या का एक तिहाई जनमानस जो कि आज गाँव में बसता हैं, उसके आर्थिक विकास का विचार दिया था। ग्रामीण विकास के लिए जनता के सहयोग से आर्थिक नीतियां बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए, लेकिन सुझावों–नीतियों को क्रियान्वित करने में चूक हुई हैं। ग्रामीणों के आर्थिक विकास का सबसे सशक्त माध्यम पशुपालन, खेती, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित कृषि से संबधित मुद्दे रहें। तत्कालीन समय में इन सब से बढकर खादी उद्योग रहा हैं वर्तमान में खादी की वास्तविक स्थिति से रूबरू होंगें तो कड़वी सच्चाई यह हैं कि कुल कपड़े के उत्पाद का एक प्रतिशत भी खादी नहीं हैं। जब कि पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से इसे लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं।

कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थिति एवं समस्या पर चर्चा से पूर्व इस उद्योग को समझना आवश्यक है–

लघु उद्योग से लोगों का अभिप्राय छोटे मोटे काम धंधे से हैं। इनमें अनेकों कांम जैसे गूड़ बनाना, मुर्गी पालना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, सिलाई करना, बकरी पालना, भैस और गाय पाल कर दुग्ध उत्पादन करना इत्यादि। अर्थात ऐसे काम जो छोटे पैमाने पर शुरू किये जाते हैं और यहॉ तक की घर से भी शुरू किये जाते हैं साधारणतया कुटीर, लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। इन उद्योगों को दो क्षेत्र में विभाजित किया जाता हैं।

- ❖ निर्माण क्षेत्र
- ❖ सेवा क्षेत्र

भारत सरकार द्वारा 1948 से अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर लगातार विशेष जोर दिया जा रहा हैं। फिर भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की सफलता में कहां चूक हुई? यह जानना आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम से ही कुटीर उद्योग खादी व ग्रामीण हस्तशिल्पियों का महत्व समझने के बावजूद स्वतंत्रता के सात दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हे उचित स्थान क्यों नहीं दे पाये हैं? इस ज्वलंत प्रश्न की तह में देखकर स्थिति को जानना होगा। सरकारी आंकडों के अनुंसार लगभग 20 प्रतिशत कपड़ें का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता हैं, शेष 80 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन मिल व पावरलूम क्षेत्र में होता हैं। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता हैं उस पर संकट के बादल घिरे रहते हैं। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांधीजी के इस सुझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपडों उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए।

लघु एवं कुटीर उद्योगों की सबसे बडी समस्या कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना और यदि इन्हे मिलता भी हैं तो बडी परेशानी के बाद ऊँचे मूल्य चुकाने के बाद। इससे इनकी लागत मूल्य बढ जाती हैं और वे अपने ऑडर का माल समय पर तैयार नहीं कर पातें। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओ का अभाव हैं। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती हैं। व्यापारिक दर पर निजी स्रोंतों से ऋण लेना पड़ता हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता को बनाये रखनें के लिए आज यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन तकनीकी का आधुनिकीकरण किया जाए। पुराने औजारों एवं प्रचीन विधियों से लघु एवं कुटीर उद्योग नवीन डिजाईन की उत्तम वस्तुओं का उत्पादन नही कर सकते । अतः उनकी निर्माण विधियों में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके सस्ती दर पर उत्तम किस्म की वस्तुएं शीघ्रता से उत्पादित की जाती हैं। उत्पादित माल के विक्रय के विषय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संगठनों की जरूरत हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों के साधन इतने सीमित होते है। कि वे विस्तृत स्तर पर विज्ञापन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकतें हैं। जिन वस्तुओं में आधुनिक मशीनी माल से प्रतियोगिता करनी होती हैं तब उनके विक्रय की व्यवस्था करना और भी कठिन हो जाता हैं।

भारतीय अर्थशास्त्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जा सकता हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार युवक बेकारी एवं अर्ध बेकारी की समस्या से परेशान हैं गांव में बेकार लोगों की संख्या बहुत अधिक हैं। बड़े पैमानें के उद्योग देश में फैले हुये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकता हैं भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक हैं जिसे कम किये बिना कृषि उद्योगों में कुशलता नहीं आ सकती हैं। अतः इतनी विशाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास किया जाए। भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा हैं कि वह एक किसान परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकतें हैं। भारत के कुछ भागों में जहां एक हीं फसल होती है वहां कृषकों की दशा और भी खराब हैं। यदि पशुपालन आदि धंधों का सहारा न मिलें तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अतः कृषि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व हैं।

पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, सूत काटना, कपडा बुनना, मधुमक्खी पालन आदि ऐसे उद्योग हैं जो सरलता से कृषि के मुख्य धंधों के साथ–साथ अपनाए जातें हैं लघु उद्योगों में श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों में छोटी मशीनों एवं विद्युत शक्ति का उपयोग किए बिना भी श्रमिक अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन कर सकता हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग हैं। कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती हैं जैसे बीड़ी बनाना, रस्सी या टोकरी बनाना आदि। छोटे उद्योग आय एवं सम्पत्ति के केंद्रीकरण को बढावा न देकर उसके विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। अतः आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण के दोषों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर कम किया जाता हैं तथा राष्ट्रीय आय का न्यायपूर्ण एवं उचित विवरण किया जा सकता हैं। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती हैं जैसें हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकडी आदि का कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढाई विभिन्न धातुओं पर नक्काशी का काम आदि। इसके लिए हस्तकौशल की आवश्यकता होती हैं। इसी प्रकार हथकरघे के उत्तम किस्म के वस्त्र भी कुटीर उद्योगों के प्रतीक हैं। देश के कुल निर्यातों में लघु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 34 प्रतिशत है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं यदि इनके तकनीकी स्तर पर सुधार किया जाए एवं बिजली से संचालित मशीनों के उपयोग की सुविधाऐं इन्हे प्रदान की जाए तो लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता हैं और राष्ट्रीय उत्पादन में इनके और अधिक योगदान की आशा की जाती हैं आजकल शहरों में बढतें हुए मूल्य स्तर के कारण मध्यवर्गीय परिवारों कों अपना जीवन स्तर कायम रखना कठिन हैं। यदि जापानी ढंग से कुछ ऐसी सरल प्रणाली अपनायी जाए जिसमें छोटी मशीनों की सहायता से उत्तम किस्म की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके तो लघु एवं कुटीर उद्योग मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं। सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में भी लधु उद्योगों के आधार पर प्रशिक्षण एवं सुविधाए प्रदान की जाए तो इससे निर्धन विद्यार्थीयों को बडा लाभ होगा। वे अपने अध्ययन को जारी रखकर उचित प्रशिक्षण प्राप्त करके राष्ट्रीय उत्पादन एवं बहुसंख्यक ग्रामीण बेरोजगारी की समाप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

देश को आजाद होने के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं प्रसार के लिए अनेक प्रकार के सरकारी उपाय किए गए हैं। इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में उद्योगों को वित्तीय सुविधाएँ, तकनीकी सुविधाएँ, विपणन सुविधाएँ प्रदान की गई है। जिसके फलस्वरूप अब भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों को भविष्य में और विकास करने की आवश्यकता हैं जिससे कृषि पर लोगों की निर्भरता कम कर उन्हे उद्योग–धंधे में लगातार प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जा सकती हैं तथा बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

भारतीय कुटीर उद्योग में सरकार के प्रयास इस प्रकार है–

- ❖ 1984 में रेशम से संबंधित अनुसंधान के उदेश्य से बेहरमपुर (कोलकाता) में केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी।
- ❖ 1948 में कॉटेज उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- ❖ अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी।
- ❖ अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी।
- ❖ अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1919 में हुई थी।
- ❖ 1990 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी।
- ❖ केन्द्रीय बिक्री संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी।

किसी भी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे के लिये उद्योगों का महत्व उतना ही हैं जितना लघु और बडे उद्योगों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सफल कुटीर उद्योगों के युवाओं के शहरों की ओर पलायन को राकते हैं। स्पष्ट है कि कुटीर उद्योगों के विकास से ही गांधी जी के गॉव में बसने वाले भारत का विकास हो पाएगा।

भारत के कुटीर उद्योगों के प्रसिद्ध केंद्र

बिहार, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू–काश्मीर भारत के रेशम उत्पादक राज्य हैं।

चंदेरी रेशम की साडी, बनारसी साडी, असम रेशम, संबलपुरी रेशम की साडी, कांचीपुरम रेशम की साड़ी, बालूमचरी साड़ी, कोनराडरेशम साड़ी, पैठणी साड़ी, पटौला साडी, रेशम साड़ी, बोम्काई रेशम की साड़ी, भागलपुर रेशम की साड़ी, ऊनी वस्त्र, चमडा, गुड एवं खांडसारी, रेशम के प्रमुख उत्पाद है।

सूक्ष्म या कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों मध्यम वर्ग के उद्योग भारतवर्ष में बडे उद्योगों के मुकाबले अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहें हैं। अक्सर अति सूक्ष्म या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्ग के उद्योग विभिन्न समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। जैसे ऋण का समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना। अगर ऋण मिल भी गया तो उस पर ज्यादा ब्याज का होना।

कच्चे माल का तुलनात्मक कीमत पर उपलब्ध होना। उत्पाद को संग्रहित रखने की उचित व्यवस्था न होना। बुनियादी जरूरतों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना जैसे अच्छी सडके होना, पानी का होना, बिजली का होना इत्यादि। इसके बावजूद लघु उद्योगों और मध्यम वर्ग के उद्योगों से सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता हैं और साल हर साल यह दर बढती जा रही हैं। अब सरकार का ध्यान भी इस ओर गया हैं और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करनें के लिये सरकार ने अनेक योजनाएँ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना भी चलाई गई हैं। हो सकता हैं कि आनें वालें समय में हमें इसके कुछ क्रांतिकारी परिणाम नजर आए।

भारत में लघु उद्योग खोलने के फायदेः–

1. लघु उद्योग खोलने के लिये आपको कम पूँजी की आवश्यकता पड़ती हैं। अर्थात आप कम पूँजी निवेश करके भी लघु उद्योग की स्थापना कर सकते हैं।

2 लघु उद्योग खोलने के लिए सरकार आपको प्रेरित करती हैं। और आपको सरकार का समर्थन हासिल होता हैं। आपके भविष्य के संवर्धन प्रक्रिया हेतु भी सरकार आपकी मदद करती हैं। जिससे अधिक लोग प्रेरित हो सकें।

3 निर्माण क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए आरक्षण विद्यमान हैं

4 वित्त संबंधी समस्याओं के लिए भी फंड और सब्सिडी विद्यमान हैं।

5 किसी विशेष खरीद पर सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाएगा।

6 समय आर्थिक विकास हेतू घरेलू बाजार की मांग में वृद्धि।

7 दुनिया के बजारों में भारतीय उत्पाद की मांग बढ सकती हैं। इसलिए भारतीय उत्पादों का निर्यात संभावित हैं।

8 लघु उद्योग स्थापित करनें के लिए मशीने, कच्चे माल, मजदूर, सस्ते दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि अधिकतर लघु उद्योग स्थानीय लोगों को लक्ष्य रखते हुए ही स्थापित किये जाते हैं । और लोगों को अपने घर के नजदीक ही काम मिल जाता हैं। इसलिए वे थोडे कम पैसे लेके भी काम करतें हैं।

कुटीर उधोग कम पूंजी में संभव होता हैं और हस्तक्रिया या हाथों द्वारा वस्तुओं को ज्यादा बनाया जाता हैं, कुटीर उधोग में पूंजी का विनियोग कम होता है, कुटीर उधोग को गाँव में खाली समय में भी उपयोग में लाया जाता हैं, जैसे– खेती के काम के बाद कुटीर उधोग, में स्थानीय माल एवं कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है और हर एक अपने सहायक धंधे के रूप में चलाते हैं जैसे– मुर्गी पालन, तालाब में मछली पालन, डेयरी, सिलाई –बुनाई, टोकरी सूप बनाना, रेशम के कीडे

पालना, रस्सी बनाना, मधुमक्खी पालन, मिटटी के बर्तन, चमडे के जूते बनाना, कोल्हू से जमल निकालना, छोटे–छोटे हस्तकरघा चलाना, ढेकी चावल इत्यादि। जब हम विकसित देशों के इतिहास को देखते हैं, तों ऐसा प्रतीत होता हैं कि एक बार में विकास नहीं हुआ हैं, बल्कि सबसे पहले कुटीर उधोगों का सहारा लेकर प्रति व्यक्ति आय को बढावा हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि हुई और वे देश जल्द ही विकसित देश की श्रेणी में आए।

कुटीर उद्योग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जाता है। ग्रामीण कुटीर उद्योग दो प्रकार के होते है। कृषि सहायक कुटीर उद्योगों में कृषि संबंधी उत्पाद की कच्चे माल कडी भूमिका निभाते है। इनमें टोकरी बनाना, सूत कातना, चावल एवं छालें तैयार करना, बीड़ी बनाना आदि उद्योग शामिल है। अन्य कुटीर उद्योगों में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिन पर कारीगरों की जीविका निर्भर करती है जैसे चटाई निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहारी का काम इत्यादि।

ग्रामीण कुटीर उद्योंग दो तरह के होते है–

(क) संगठित एवं (ख) असंगठित

(क) संगठित ग्रामीण कुटीर उद्योग

संगठित ग्रामीण कुटीर उद्योग वैसे उद्योग को कहते है जो पंजीकृत होते है। जिसके कारण सरकार से सहायता राशि भी उपलब्ध होती है और काम सुचारू रूप से चलता है। जिसमें सालों भर काम रहता है एव ंसाल के हर एक मौसम में इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की माँग रहती है।

(ख) असंगठित ग्रामीण कुटीर उद्योग

असंगठित ग्रामीण कुटीर उद्योग वैसे उद्योग को कहते है जो पंजीकृत नहीं होते है जिसके कारण सरकार से सहायता राशि नहीं मिलती है जिसके कारण काम बन्द हो जाता है और वस्तुओं को बाहर बेचने के रास्ते भी बन्द हो जाते है। जिसमें साल के कुछ महिने ही काम रहता है एवं कुछ महीने ही काम रहता है एवं इसके द्वारा बनाए गए उत्पादों की माँग हमेशा नहीं रहती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि एवं पशुपालन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लागों की आजीविका का प्रमुख साधन कुटीर उद्योग ही है। प्रस्तुत शोध–प्रारूप का महत्व संगठित ग्रामीण कुटीर उद्योग के बारे में अध्ययन किया जाएगा।

राठौर भारती (1999), ''गामीण लघु उद्योंगों की उत्पादकता एवं विपणन का अध्ययन'' के अन्तर्गत यह निष्कर्ष निकाला है कि हस्तशिल्प उद्योंगों में उत्पादन में कमी हुई है। इसका मुख्य कारण फैशन, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा गुणवत्ता में परिवर्त्तन के कारण इन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा। जिससे रोजगार प्रभावित हुआ। अतः हस्तशिल्प उद्योंगों को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उच्च तकनीकी तथा सरकार द्वारा स्थानीय कारीगरों को समय–समय पर फैशन में भागीदारी के अनुसार प्रशिक्षत दिया जाना चाहिए।

डॉ0 मिश्र (2003), ''ग्रामीण कुटीर उद्योंगों पर तकनीकी प्रभाव'' के अतर्गत किये गये शोध के निष्कर्ष में कहा कि इस बदलती हुई परिस्थितियों में तैयार वस्त्र निर्माण उद्योग बहुत ही प्रतिस्पर्धा और कठिनाई के दौर में विद्युत से चलने वाले करधों के द्वारा वस्त्र निर्माण की गुणवत्ता में सुधार कम हुआ है। अन्य बड़े उद्योग की तुलना में उसकी दक्षता कम होने से कुटीर उद्योगों की स्थिति खराब होती जा रही है।

हेमा गाँधी (2009) '' हस्तशिल्प कला से रोजगार'' हेमा गाँधी ने हस्तशिल्प कला से मिलने वाले रोजगार पर अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि आज भी देश में अधिकांश जनता को घर बैठे रोजगार नही मिल रहा है तथा ग्रामीण इलाकों में भी लोगों द्वारा कई प्रकार के आकर्षक वस्तुओं को तैयार कर बाजार में बेची जाती है और अधिकांश लोगों की रोजी–रोटी इसी उद्योगों से मिल रहा है।

मुकेश कुमार (2011) लघु एवं कुटीर उद्योंग ने अपने पुस्तक में कम से कम पुँजी में आरम्भ होने वाले लघु एवं कुटीर उद्यों की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

डॉ0 डी रेड्डी (2008) लघु उद्योग ग्रामीण रोजगार का स्रोत के साथ आय का साधन के रूप में जाना जाता है।

लघु उद्यम की इकाइयों की संख्या, निवेश और रोजगार का व्यौरा

(2021–2022 और 2022–2023)

डद्यमों की श्रेणी	इकइयों की संख्या		निवेश(करोड़ रू0 में)		रोजगार (संख्या)	
	2022–2023	2023–2024	2022–2023	2023–2024	2022–2023	2023–2024
अतिलघु	196	448	250.2	1577.8	5451	11596
लघु	111	199	684.02	1373.7	8560	31070

स्रोत– बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024–2025

इस प्रकार 2022–2023 में अतिलघु एवं लघु बड़ी संख्या में अपना काम किया है, जो लघु उद्यम के विकास को दर्शता है।

बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 के तहत आवेदन आवेदन एवं एवं चषनित उद्वमियों की स्थिति

योजना के लाभार्था	2018–19 से 2021–21		2021–22		2022–23		2023–24	
	प्राप्त आवेदन की संख्या	चयनित आवेदन की संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	चयनित आवेदन की संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	चयनित आवेदन की संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या	चयनित आवेदन की संख्या
टनुसूचित जाति/जन जाति	53997	5120	13726	3999	48956	2047	47858	1959
अति पिछड़ी जाति	17004	1978	17640	4000	63864	2020	71404	1800
युवा उद्यमी	––	––	17820	3987	67487	2080	71924	1882
महिला उद्यमी	––	––	13138	4000	43556	1964	42993	1977
अल्पसंख्यक उद्यमी	––	––	––	––	––	––	28260	1236

स्रोत– बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024–2025

इस प्रकार बिहार स्टार्ट–अप नीति के तहत लगातार उद्यमियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लघु एवं कुटिर उद्योग उद्योग को बाजार में बने रहने के लिए नए नए तकिनीक और फैशन से जुड़कर रहना होगा। लघु एवं कुटीर उद्योग से ग्रामीणों को रोजी रोटी मिलती है। एवं अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएँ प्राप्त होती है।

निष्कर्ष

जहाँ एक ओर बिहार में लघु उद्योग की स्थिति तेजी से सुधर रही है। 2023–24 में इस क्षेत्र में 135: की वृद्धी दर्ज की गई है। हालांकि इसमें स्वरोजगार में वृद्धि एवं विनिर्माण में कमी कमी दिखती है। राज्य सरकार की योजनाओं से उद्यमिता विकास में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ भी है। लघु एवं कुटिर उद्योग एवं उद्योग को बाजार में बने रहने के लिए नए नए तकिनीक और फैशन से जुड़ाव कम है। बड़े उद्योग की तुलना में लघु उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार कम हो पा रहा है जिससे लघु एवं कुटीर उद्योगों की

स्थिति में सुधार कम हो रहा है। उद्यमिता विकास योजनाओं में लाभार्थियों को समय पर किस्त का भुगतान नहीं होता है।

संदर्भ

1. राठौर भारती ''गामीण हस्तशिल्प उद्योंगों की उत्पादकता एवं विपणन का अध्ययन'' प्रकाशित लेख 1999
2. डॉ0 मिश्र, ''ग्रामीण कुटीर उद्योंगों पर तकनीकी प्रभाव'' शोध प्रबंध 2003
3. गाँधी हेमा '' हस्तशिल्प कला से रोजगार'' प्रकाशित लेख 2009
4. कुमार मुकेश '' लघु एवं कुटीर उद्योग, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली 2011
5. मुखर्जी, रविन्द्र'' सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. कुरूक्षेत्र, जुलाई 2018 निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली
7. योजना, मई 2018, योजना भवन, संसद मार्ग,, नई दिल्ली।
8. जनगणना रिर्पोट 2011
9. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024.25